



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त, 2009

भाद्रपद 5, 1931, शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1230/79-वि-1-09-1(क)21-2009

लखनऊ, 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहल जायेगा। रक्षित नाम और
गारंटी
- (2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 5 सन
2008 की धारा
49 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जाएगा है की धारा 49 को निकाल दिया जायेगा।

धारा 50 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“(1) कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर कारबार के सम्बन्ध में अनुसूची-1 में निर्दिष्ट एवं वर्णित वस्तुओं से गिन्त ऐसी मात्रा या माप या मूल्य का माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस गिन्त अधिसूचित किया जाय, लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो या तो निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र पर हो जहाँ इस व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहाँ पर साधारणतया वह निवास करता है यथाविहित रीति से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा या यथाविहित रीति से विभागीय वेब साइट से डाउनलोड करेगा

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से गिन्त प्रयोजनों के लिए ऐसी माल को लाने आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।”

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रवासी व्यक्ति गाड़ी को धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर रोकेंगा और उसे तब तक रोक रखेगा जब तक कि यथास्थिति धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का तथा पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाय तो उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के रजिस्ट्रार और माल के पारंपरिक और पारिवर्तिक नाम और पता देगा।”

धारा 52 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

“52-जब राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर राज्य से होकर किसी अन्य स्थान को आने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रवासी व्यक्ति राज्य में ऐसे दस्तावेजों को रखेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा न करने पर वह गान लिया जायेगा कि उसे द्वारा ले जाने वाला माल गाड़ी के रजिस्ट्रार या प्रवासी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेचने के लिए है।”

धारा 54 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (1) में उपधारा 9 और उपधारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा क्रमशः सम्मिलित रख दी जायेगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
9	यथार्थि, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है।	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि।
15.	जहाँ, यथार्थि, चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति,— (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ में रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है; या (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है; या	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत।
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होता है, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है; या	
	(चार) परिवहक या वाहन या भाड़ेदार होते हुये, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो;	

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रह के लिए मूल्य संवर्धित व्यवस्था को प्रारम्भ करने हेतु उपबन्धित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जाँच चौकियों और नाकों के कारण व्यक्तियों, जिनमें व्यापारी एवं उद्यमी सम्मिलित हैं, को होने वाली असुविधा को दूर करने तथा अबाध व्यापार एवं वाणिज्य को सुगम बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय,

(क) जाँच चौकियों और नाकों की स्थापना के प्रावधान को निकाल दिया जाए,

(ख) व्यापारी को विभागीय वेबसाइट से आयात हेतु घोषणा का प्रपत्र डाउन लोड करना अनुमत्त किया जाय,

(ग) राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को ले जाने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में उल्लिखित माल ले जाने वाली गाड़ी के चालक या वाहन प्रभारी, अन्य व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों को रखने की अपेक्षा करना जैसे विहित किये जाय।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1230 (2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka)-21-2009

Dated Lucknow, August 27, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Samanya 22 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 26, 2009.

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT)
ACT, 2009.

(U.P. ACT NO. 22 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:-

short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2009.

(2), It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment
of section 49
of U.P. Act
no. 5 of 2008
Amendment
of section 50

2. Section 49 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principle Act, shall be omitted.

3. In section 50 of the principle Act,—

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place outside the State any goods other than the goods named and described in Schedule-I in such quantity or measure or of such value, as may be notified by the State Government in this behalf, in connection with business, shall either obtain the prescribed form of declaration in such manner as may be prescribed from the assessing authority having jurisdiction over the area, where his principle place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides or shall download from official web site of the department in such manner as may be prescribed:

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate.”

(b) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(3) The driver or other person-in-charge of any vehicle carrying any goods referred to in the preceding sub-sections shall stop the vehicle when so required by an officer authorised under sub-section (1) of section 45 or sub-section (1) of section 48 and keep it stationary for so long as may be considered necessary by the officer authorised under sub-section (1) of section 45 or sub-section (1) of section 48, as the case may be, and allow him to search the vehicle and inspect the goods and all documents referred to in the preceding sub-sections and shall, if so required, give his name and address and the names and addresses of the owner of the vehicle and of the consignor and the consignee of the goods."

4. For section 52 of the principal Act, the following section shall be *substituted*,
namely : Amendment of
section 52

"52. When a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State and carrying goods referred to in sub-section (1) of section 50, passes through the State, the driver or other person in charge of such vehicle shall carry such documents as may be prescribed failing which it shall be presumed that the goods carried thereby are meant for sale within the State by the owner or person in charge of the vehicle."

5. In section 54 of the principle Act, in sub-section (1), in the table for the entries at serials 9 and 15 the following entries shall *column-wise* be *substitute* 1, respectively,
namely :- Amendment of
section 54

(1)	(2)	(3)
"9	The dealer or other person, as the case may be, obstructs or prevents an officer empowered under section 45 or section 48 from performing any of his functions under this Act;	A sum of rupees five thousand in case of registered dealer and five times thereof in case of others
15.	Where the driver or person in charge of the vehicle, as the case may be,-	40% of the value of goods
	(i) fails to carry documents referred to in section 52 and also fails to prove that goods carried in his vehicle are meant for delivery to dealers or persons outside the State; or	
	(ii) while carrying such documents for transit of goods through the State undertakes responsibility of 'handling over such goods to a bonafide person inside the State for carrying them outside the State but fails to hand over such goods to such bonafide person; or	
	(iii) being a person, who receives any goods from driver or person in charge of a vehicle for carrying them outside the State, does not carry such goods outside the State; or	
	(iv) being a transporter or hirer of a vehicle prepares goods-receipt by showing false destination of goods outside the State;"	

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for introducing Value Added System of taxation for levy and collection of tax on sale or purchase of goods. With a view to removing inconvenience to persons including traders and entrepreneurs due to check-posts and barriers established under the said Act and for facilitating free trade and commerce, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for:-

- (d) omitting the provisions for the establishment of check-post and barriers;
- (e) allowing the dealer to download the Form of declaration for import, from the official website of the department;
- (f) requiring the driver or other person in charge of the vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State and carrying goods mentioned in sub-section (1) of section 50, to carry such documents as may be prescribed.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.